11/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **लोकसभा चुनाव में नौकरियाँ, मुद्रास्फीति प्रमुख मुद्दे, सर्वेक्षण 11 अप्रैल (GS PAPER III: रोजगार)**
2. **उच्चतम न्यायालय ने डीएमआरसी के खिलाफ ₹7,687 करोड़ के पुरस्कार को 'पूरी तरह से अवैध' बताकर रद्द कर दिया (11 अप्रैल) (GS PAPER II: उपचारात्मक याचिका/शक्ति)**
3. **कच्चातिवू लीक से हटकर सोचने की मांग करता है (11 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)**
4. **भानुमती का पिटारा: चुनावी बांड योजना पर, उभरते विवरण (11 अप्रैल) (GS PAPER II: चुनाव)**
5. **' के लिए समग्र दृष्टिकोण का आगमन (11 अप्रैल) (GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)**

PatriotICAS

लोकसभा चुनाव में नौकरियाँ, मुद्रास्फीति प्रमुख मुद्दे, सर्वेक्षण 11 अप्रैल (GS PAPER III: रोजगार)

मुस्लिम, दलित और आदिवासी इन मुद्दों को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं; सभी इलाकों में सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से लगभग दो-तिहाई (62%) ने कहा कि काम पाना बहुत मुश्किल हो गया है

- 2024 के आम चुनावों से पहले सीएसडीएस- लोकनीति द्वारा किए गए एक चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण में **लगभग आधे मतदाताओं के बीच बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को प्रमुख चिंताओं के रूप में उजागर किया गया था।**
- **सर्वेक्षण में शामिल लगभग 62% लोगों ने व्यक्त किया कि नौकरी पाना अधिक कठिन हो गया है, सबसे अधिक चिंता शहरों (65%) में देखी गई।**
- नौकरी खोजने में कठिनाई सभी इलाकों में उल्लेखनीय थी, गांवों में 62% और कस्बों में 59% ने यही भावना व्यक्त की।
- पुरुषों में, **59% महिलाओं की तुलना में, 65% को लगता है कि नौकरी पाना कठिन हो गया है। केवल 12% का मानना था कि नौकरी ढूंढना आसान हो गया है।**
- नौकरी की कमी के बारे में चिंता विशेष रूप से मुसलमानों (67%) के बीच अधिक थी, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति (63% प्रत्येक), और अनुसूचित जनजाति (59%) के हिंदू थे।
- इसके विपरीत, **17% हिंदू ऊंची जातियों को लगा कि नौकरियां प्राप्त करना आसान है, जबकि 57% असहमत थे।**
- मूल्य वृद्धि के संबंध में, **71% उत्तरदाताओं का मानना था कि कीमतें बढ़ी हैं, गरीबों, मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के बीच यह प्रतिशत बढ़कर 76% हो गया है।**
- कई मतदाताओं ने नौकरी के अवसरों में कमी के लिए राज्य सरकारों (17%) और केंद्र (21%) दोनों को जिम्मेदार ठहराया।
- इसी तरह, मूल्य वृद्धि के मुद्दे के लिए **26% ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, 12% ने राज्य सरकारों को दोषी ठहराया और 56% ने इसके लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया।**

जीवन स्तर

- पिछले पांच वर्षों में, **लगभग 48% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि उनके जीवन की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार हुआ है, जबकि 14% ने कोई बदलाव नहीं बताया, और 35% ने गिरावट का संकेत दिया।**
- केवल 22% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और अपनी घरेलू आय से पैसे बचा सकते हैं। अन्य लोगों को विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा: 36% बचत नहीं कर सके लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, 23% को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और 12% अपनी जरूरतों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सके ।
- **एक महत्वपूर्ण बहुमत (55%) का मानना था कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 2019 के सर्वेक्षण से वृद्धि हुई है जहां 40% ने इस विचार को साझा किया। केवल 19% का मानना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, जो 2019 में 37% से कम है।** जिन लोगों ने वृद्धि देखी, उनमें से **25% ने केंद्र को दोषी ठहराया, 16% ने राज्यों को दोषी ठहराया, और 56% ने दोनों को दोषी ठहराया।**
- इन चिंताओं के बावजूद, **लगभग आधे उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षों में विकास समावेशी रहा है।**

गुमनाम होर्डिंग्स पर चुनाव आयोग की कार्रवाई (11 अप्रैल)

- चुनाव आयोग (ईसी) ने गुमनाम राजनीतिक होर्डिंग्स को संबोधित करने के लिए कार्रवाई की है।
- चुनाव आयोग ने इन होर्डिंग्स के प्रकाशकों और मुद्रकों के नामों का खुलासा करने का अनुरोध किया है।
- यह खुलासा अभियान के वित्तपोषण को विनियमित करने और व्यक्तियों को जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है।
- होर्डिंग्स सहित मुद्रित मतदान-संबंधित सामग्रियों पर प्रिंटर और प्रकाशकों की स्पष्ट पहचान अनिवार्य है।
- नगर निगम अधिकारियों द्वारा नियंत्रित स्थानों पर गुमनाम होर्डिंग्स के बारे में शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया गया था।
- लक्ष्य पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से उस सामग्री से संबंधित जो आदर्श आचार संहिता या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव, पतंजलि की माफी से इनकार किया (11 अप्रैल)

- सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की दूसरे दौर की माफी को खारिज कर दिया।
- अदालत ने फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों के बारे में चिंता व्यक्त की, जो संभावित रूप से अपने उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जनता को गुमराह कर रही हैं।
- न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि आशाजनक दावों के साथ विज्ञापित उत्पादों के लिए भुगतान करने के बावजूद उपभोक्ताओं को अक्सर अपने स्वास्थ्य को नुकसान उठाना पड़ता है।
- कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापनों की आलोचना की .

PatriotICIAS

- नवंबर 2023 में अदालत को दिए गए एक उपक्रम का उल्लंघन करने के लिए 27 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद और श्री बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी ।
- उपक्रम में कहा गया कि वे 1954 अधिनियम के उल्लंघन में "इलाज" का विज्ञापन करने से परहेज करेंगे।
- न्यायमूर्ति कोहली ने माफी की ईमानदारी पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि पिछले वचन के उल्लंघन को देखते हुए इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है।

राज्य पर गुस्सा

- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को नजरअंदाज करने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी की आलोचना की.
- न्यायमूर्ति कोहली ने प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनकी निष्क्रियता के लिए उन्हें दंडित किया।
- अदालत ने इस मुद्दे को संबोधित करने में प्राधिकरण की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि वे उदासीन या निष्क्रिय थे।
- आयुर्वेद और श्री बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का मामला 16 अप्रैल को निर्धारित किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने डीएमआरसी के खिलाफ ₹7,687 करोड़ के पुरस्कार को 'पूरी तरह से अवैध' बताकर रद्द कर दिया (11 अप्रैल) (GS PAPER II: उपचारात्मक याचिका/शक्ति)

- सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को ₹7,687 करोड़ का भुगतान करना था।
- इस फैसले को डीएमआरसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए चुनौती दी थी।

भारतीय संविधान के किसी भी विशिष्ट अनुच्छेद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय, इसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है, विशेषकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।
सुप्रीम कोर्ट ने **रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य (2002) के ऐतिहासिक मामले में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को मान्यता दी।**
यह न्याय में भारी गड़बड़ी को ठीक करने या प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत को संबोधित करने के लिए उपलब्ध एक असाधारण कानूनी उपाय है।
उपचारात्मक याचिका का कानूनी आधार मुख्य रूप से भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों में निहित है** , जो अदालत को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

- तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि डीएमआरसी को 2017 के मध्यस्थ फैसले से "न्याय की गंभीर हानि" का सामना करना पड़ा।

PatriotiCAS

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के फैसले को भी पलट दिया, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच से असहमति जताते हुए मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा था।
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 2021 में अदालत के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि इसने सार्वजनिक उपयोगिता पर अत्यधिक दायित्व का बोझ डालने वाले एक अवैध पुरस्कार को बहाल कर दिया है।
- डीएमआरसी के तर्क में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि न्यायाधिकरण ने समझौते की समाप्ति का आकलन करते समय आयुक्त मेट्रो रेल सुरक्षा (सीएमआरएस) प्रमाणन से महत्वपूर्ण सबूतों की उपेक्षा की।
- पीठ ने पिछले निर्णयों में सीएमआरएस प्रमाणपत्र की प्रासंगिकता की गलत व्याख्या को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी के रुख से सहमति व्यक्त की।
- नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए निष्पादन कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया और 2021 के फैसले के बाद डीएमआरसी द्वारा जमा की गई किसी भी राशि की वापसी को अनिवार्य कर दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'खतरनाक' कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के परिपत्र को रद्द कर दिया (11 अप्रैल)

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को केंद्र द्वारा जारी एक परिपत्र को अमान्य कर दिया, जिसमें "क्रूर और खतरनाक" कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्र के पास एक परिपत्र के माध्यम से कुत्तों की नस्लों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 या पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों द्वारा सशक्त नहीं था।
- न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने बेंगलुरु के निवासी किंग सोलोमन डेविड और मार्डोना जोन्स की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया ।
- सभी हितधारकों से परामर्श के बाद कुछ कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जनहित याचिका याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का वादा करने वाले केंद्र द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के बावजूद, हितधारकों के साथ परामर्श के बिना परिपत्र जारी किया गया था।
- हालांकि अदालत ने परिपत्र को रद्द कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि केंद्र अभी भी प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों में संशोधन कर सकता है, लेकिन हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए, जिसमें कुत्तों की नस्लों को प्रमाणित करने वाले संगठन और पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) जैसे पशु अधिकार समूह शामिल हैं।
- अदालत ने पालतू जानवरों के मालिकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया कि वे अपने कुत्तों के कारण होने वाली किसी भी चोट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें, जिसमें पीड़ितों के इलाज की लागत भी शामिल है।
- प्रतिबंधित कुत्तों की कुछ नस्लों में **पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर शामिल हैं**। और कुत्तों को आमतौर पर बैन डॉग या बैंडोग के नाम से जाना जाता है।

PatriotICAS

कच्चातिवू लीक से हटकर सोचने की मांग करता है (11 अप्रैल) (GS PAPER II: आईआर)

पाक जलडमरूमध्य में बर्लिन की दीवार बनाने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण होगा; इसके बजाय, पाक खाड़ी को भारत और श्रीलंका की साझी विरासत के रूप में सोचा जाना चाहिए

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान श्रीलंका के साथ भारतीय मछुआरों के मुद्दे को संबोधित करने का काम पोन राधाकृष्णन को सौंपा था।
- राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में इस मामले पर चर्चा करने के लिए लेखक के साथ रामेश्वरम के 200 मछुआरों को आमंत्रित किया।
- भाजपा मुख्यालय में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान, मछुआरों ने कच्चातिवू के आत्मसमर्पण और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को गोली मारने के बारे में बात की।

- लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी मछुआरे ने मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया: **श्रीलंकाई तमिल मछुआरों के अपने पानी में मछली पकड़ने का अधिकार।**
- तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे का मूल कारण कच्चाथीवू मामले को फिर से खोलने की अनिच्छुक सरकारों और अपनी आजीविका छोड़ने के अनिच्छुक भारतीय मछुआरों के बीच हितों का टकराव है।
- द्विपक्षीय समझौतों को एकतरफा रद्द करने से भारत-श्रीलंका संबंधों और अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते महत्व रखते हैं और इन्हें मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता है।
- केंद्र को **बाधाएं पैदा करने के बजाय पाक जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए** , क्योंकि भारत और श्रीलंका की भलाई आपस में जुड़ी हुई है।

शांतिपूर्ण समाधान की तलाश

- लेखक ने मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने के उद्देश्य से 1990 के दशक की शुरुआत में कच्चातिवु के मुद्दे पर शोध करना शुरू किया।
- कच्चाथीवू से संबंधित प्राथमिक स्रोत अप्राप्य थे क्योंकि उन्हें नई दिल्ली ने ले लिया था, और उस समय कोई सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं था।
- **1974 में, अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विपक्ष में थे, ने लोकसभा में एक बहस के दौरान कच्चातिवु को उपहार में देने की तुलना भूमि दान (भूदान) से की।**
- भाजपा नेता जना कृष्णमूर्ति ने न्यायिक उपचार की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर करने का प्रयास किया, लेकिन रामनाद के राजा द्वारा कच्चातिवु के स्वामित्व को साबित करने वाले सबूतों की कमी के कारण असफल रहे ।

PatriotIAS

लेखक ने दो समाधान प्रस्तावित किये:

- **कच्चाथीवु को हमेशा के लिए पट्टे पर प्राप्त करें , जिससे भारत श्रीलंका की संप्रभुता को बरकरार रखते हुए मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग कर सके।**
- **भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जलक्षेत्र में पांच समुद्री मील तक मछली पकड़ने की अनुमति दें, जैसा कि श्रीलंकाई मछुआरों को वाड्ज बैंक के पास मछली पकड़ने की अनुमति देने वाले समझौतों के समान है।**

- तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक और द्रमुक दोनों सरकारों ने लेखक के सुझावों का समर्थन किया, लेकिन इस मुद्दे को फिर से खोलने से नई दिल्ली के इनकार ने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की।

ट्रॉलिंग का परिचय

- 1960 और 1970 के दशक में, भारत को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, और इंदिरा गांधी ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित किया, जिससे **झींगा मछली पकड़ने के लिए पाक खाड़ी में बॉटम ट्रॉलर की शुरुआत हुई।**
- श्रीलंका में जातीय संघर्ष ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में गहराई तक जाने की अनुमति दी, जिसकी सुविधा शरणार्थी के रूप में कार्यरत श्रीलंका के तमिल मछुआरों ने दी।
- **निचले ट्रॉलरों ने समुद्र तल को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे पाक खाड़ी के भारतीय हिस्से में मछली की उपलब्धता कम हो गई और भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।**

नीचे ट्रॉलिंग

- बॉटम ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की एक विधि है जहां मछली और अन्य समुद्री जीवन को पकड़ने के लिए एक बड़े, भारी जाल (ट्रॉल) को समुद्र तल पर खींचा जाता है।
- इसके दो मुख्य प्रकार हैं:
- **बेन्थिक ट्रॉलिंग:** समुद्र के बिल्कुल नीचे तक जाल खींचती है।
- **डीमर्सल ट्रॉलिंग:** समुद्र तल के ठीक ऊपर जाल खींचकर तल के करीब रहने वाली प्रजातियों (जैसे कॉड या स्किड) को लक्ष्य करता है।

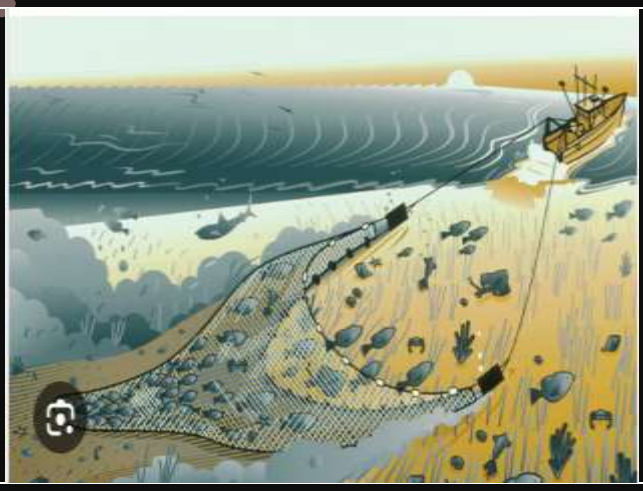

बॉटम ट्रॉलर के घटक

- **मछली पकड़ने का जहाज़:** भारी सामान खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली एक विशेष जहाज़।
- **चरखी:** ट्रॉल जाल को लपेटने और तैनात करने के लिए शक्तिशाली चरखी।
- **ट्रॉल नेट:** कैच पकड़ने के लिए एक बंद सिरे (कोडेंड) वाला एक बड़ा, शंकु के आकार का जाल।

PatriotIAS

- **ओटर बोर्ड (ट्रॉल दरवाजे):** इसे क्षैतिज रूप से और समुद्र तल पर खुला रखने के लिए जाल से जुड़े भारी दरवाजे।
- **ग्राउंड गियर (बॉटम टेंडिंग गियर):** नेट के नीचे रोलर्स, चेन या बॉबिन, कभी-कभी जानबूझकर समुद्र तल को परेशान करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
- **बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में चिंताएँ**
- **पर्यावास का विनाश:** निचली ट्रॉलिंग मूंगा चट्टानों और समुद्री घास के बिस्तर जैसे नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे समुद्री जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।
- **बायकैच:** यह अभ्यास बड़ी मात्रा में गैर-लक्षित प्रजातियों को पकड़ता है, जिनमें किशोर और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं, जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है।
- **अत्यधिक मछली पकड़ना:** निचले स्तर पर मछली पकड़ने के अस्थिर स्तर के कारण मछली का स्टॉक कम हो सकता है।

प्रबंधन और विनियमन

- **मछली पकड़ने के क्षेत्र:** कई देशों ने ऐसे क्षेत्र निर्दिष्ट किए हैं जहां संवेदनशील आवासों की रक्षा के लिए नीचे की ओर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है या प्रतिबंधित है।
- **गियर संशोधन:** अनुसंधान का ध्यान बायकैच को कम करने और समुद्र तल में अशांति को कम करने के लिए ट्रॉल संशोधनों पर केंद्रित है।
- **कोटा और पकड़ सीमाएँ:** कुल स्वीकार्य पकड़ को विनियमित करने से विशिष्ट प्रजातियों की अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकने में मदद मिलती है।

- **श्रीलंका में बॉटम ट्रॉलरों पर प्रतिबंध होने के बावजूद, भारतीय ट्रॉलर वहां काम करते रहे, जिसके कारण श्रीलंकाई मछुआरों ने समुद्र तल को नष्ट करने की शिकायतें कीं।**
- भारत की श्रीलंका नीति श्रीलंकाई प्रधान मंत्री के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर केंद्रित थी, जिसके कारण कुछ अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद, 1974 में कच्चाथीवू को सौंप दिया गया।
- सौंपने पर एम. करुणानिधि की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया गया, क्योंकि उन्होंने बेरुबारी के संबंध में बीसी रॉय की तरह कानूनी कार्रवाई नहीं की थी ।
- कच्चातीवू पर नियंत्रण हासिल कर भी लेता है , तो भी भारतीय मछुआरों के सामने आने वाली समस्याएं बनी रहेंगी, जिनमें श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश करना और प्रतिबंधित बॉटम ट्रॉलर का उपयोग शामिल है।
- यदि श्रीलंका **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के खिलाफ मामला दायर करता है** , तो भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, **जैसा कि फिलीपींस के साथ चीन के मामले में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप चीन के खिलाफ नकारात्मक फैसला आया था** ।
- कच्चाथीवु के बारे में चिंता जताने वाले तमिलनाडु के राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि भारतीय मछुआरों के सामने आने वाली समस्याएं केवल क्षेत्रीय नियंत्रण के मुद्दे के बजाय उनकी गतिविधियों और बॉटम ट्रॉलर के उपयोग से उत्पन्न होती हैं।

साहसिक निर्णयों की आवश्यकता

- पाक खाड़ी क्षेत्र में चुनौतियाँ नवीन समाधानों के अवसर प्रस्तुत करती हैं।
- **पाक खाड़ी को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल के रूप में देखा जाना चाहिए।**
- **पाक खाड़ी को परिवर्तित करने का प्रस्ताव एक साझा विरासत क्षेत्र में, भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों दोनों के लिए समुद्री संसाधनों तक समान पहुंच की अनुमति।**
- भारत सरकार को निष्पक्ष मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

PatriotIAS

- **प्रस्तावित फॉर्मूला: श्रीलंकाई मछुआरे तीन दिन, भारतीय मछुआरे तीन दिन मछली पकड़ेंगे, जिसमें एक दिन छुट्टी होगी।**
- **दोनों देशों के तमिल मछुआरों को सहकारी समितियां बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्यम में एक साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।**
- एक मातृ जहाज की सहायता के लिए ट्रॉलरों को जहाजों में संशोधित करना, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना और भारतीय समकक्षों के कारण तमिल मछुआरों की आजीविका को हुए नुकसान की मरम्मत करना।
- क्षेत्र में जीत-जीत के परिणाम के लिए साहसिक पहल पर जोर।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सवाल: कच्चाथीवु मुद्दे से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान चुनौतियों और भारत-श्रीलंका संबंधों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। कच्चाथीवु मुद्दे को संबोधित करने और पाक खाड़ी क्षेत्र में मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने में, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेताओं की भूमिका का विश्लेषण करें । (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण:

- कच्चाथीवु मुद्दे से जुड़ी संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान चुनौतियों के साथ उत्तर का परिचय दें ।
- फिर भारत-श्रीलंका संबंधों पर इसके तनाव और स्थानीय समुदायों के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख करें।
- कच्चातिवू मुद्दे को संबोधित करने में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक नेताओं की भूमिका का उल्लेख करें ।
- फिर आगे का रास्ता लाओ.
- अंत में दोनों पक्षों के मछुआरों की चिंताओं को दूर करने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर बातचीत और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

उत्तर:

कच्चाथीवू मुद्दा, भारत-श्रीलंका संबंधों और पाक खाड़ी क्षेत्र में मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करने वाली एक लंबे समय से चुनौती रही है । इस क्षेत्रीय विवाद के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और तनाव बढ़ गया है। इस मुद्दे के समाधान के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेताओं के प्रयासों के बावजूद, एक स्थायी समाधान खोजना मायावी बना हुआ है।

कच्चाथीवु मुद्दे को संबोधित करने में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक नेताओं की भूमिका

- ऐतिहासिक रूप से, श्रीलंका को कच्चातिवू उपहार में देने का भारत के भीतर विरोध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने संसदीय बहस के दौरान इसकी तुलना भूमि दान के रूप में की थी।
- हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय में मामले दायर करने जैसे न्यायिक उपायों की तलाश के बाद के प्रयास, रामनाद के राजा द्वारा स्वामित्व साबित करने वाले सबूतों की कमी के कारण असफल रहे ।
- क्षेत्रीय नियंत्रण के मुख्य मुद्दे को संबोधित करने में विफलता ने भारतीय मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों को बरकरार रखा है।

- कच्चातिवु मुद्दे से जुड़ने का प्रयास किया है।
- हालाँकि, चर्चाओं को फिर से खोलने और द्विपक्षीय समझौतों पर फिर से बातचीत करने के प्रयासों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।
- भारतीय मछुआरों की अपनी आजीविका छोड़ने की अनिच्छा, तमिलनाडु में स्थानीय समुदायों के लिए मुद्दे की संवेदनशीलता के साथ मिलकर, समाधान प्रक्रिया को जटिल बनाती है।

PatriotIAS

आगे बढ़ने का रास्ता

- पाक खाड़ी क्षेत्र में मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने और भारत-श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए साहसिक और अभिनव समाधानों की आवश्यकता है।
- एक प्रस्तावित दृष्टिकोण पाक खाड़ी को एक साझा विरासत क्षेत्र के रूप में देखना है, जिससे भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों दोनों के लिए समुद्री संसाधनों तक समान पहुंच हो सके।
- इसमें निष्पक्ष मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना और दोनों पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक घूर्णी मछली पकड़ने के कार्यक्रम को लागू करना शामिल हो सकता है।
- इसके अलावा, सहकारी समितियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से दोनों देशों के तमिल मछुआरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से एकजुटता और पारस्परिक लाभ की भावना को बढ़ावा मिल सकता है।
- इसके अतिरिक्त, एक मातृ जहाज की सहायता के लिए ट्रॉलर को जहाजों में संशोधित करना और भारतीय समकक्षों के कारण होने वाली क्षति की मरम्मत करना, बॉटम ट्रॉलिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।

इस प्रकार, कच्चाथीवु मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करते हुए पाक खाड़ी के दोनों किनारों पर मछुआरों की आजीविका को प्राथमिकता दे। क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए निरंतर बातचीत और साहसिक पहल आवश्यक हैं।

भानुमती का पिटारा: चुनावी बांड योजना पर, उभरते विवरण (11 अप्रैल) (GS PAPER II: चुनाव)

- भारतीय स्टेट बैंक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दान की जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया था।
- द हिंदू सहित जांच परिणामों से पता चला कि **2016-17 से 2022-23 तक कुल घाटे में ₹1 लाख करोड़ से अधिक वाली 33 कंपनियों ने ₹582 करोड़ के करीब दान दिया, जिसमें से 75% सत्तारूढ़ भाजपा को दिया गया।**
- **चिंताएँ पैदा होती हैं क्योंकि घाटे में चल रही कंपनियों ने महत्वपूर्ण रकम दान की, लाभ कमाने वाली कंपनियों ने दान में अपने कुल लाभ को पार कर लिया, और कुछ दाता कंपनियों ने शुद्ध लाभ या प्रत्यक्ष करों पर डेटा की रिपोर्ट नहीं की।**
- **नई निगमित फर्मों ने निर्धारित तीन साल की अवधि से पहले दान दिया, जिससे नियम तोड़ने और संदिग्ध फंडिंग स्रोतों का संदेह पैदा हुआ।**
- **इस बारे में प्रश्न बने हुए हैं कि क्या घाटे में चल रही ये कंपनियाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मुखौटा थीं, क्या लाभ/नुकसान की रिपोर्ट नहीं करने वाली कंपनियाँ शेल कंपनियाँ थीं, और क्या लाभदायक दाता फर्मों ने करों की चोरी की थी।**

काले धन को वैध बनाना

- मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की अवैध उत्पत्ति (अपराध, भ्रष्टाचार आदि से लाभ) को छिपाने और ऐसा दिखाने की प्रक्रिया है जैसे कि यह वैध स्रोतों से आया हो।
- इसमें धन के लेन-देन को छिपाने और उसके वास्तविक स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए लेन-देन की एक श्रृंखला शामिल है।

नाम भर की कंपनियां

- **शेल कंपनियां निगम या अन्य व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो कागज पर मौजूद हैं लेकिन उनके पास कोई वास्तविक कार्यालय स्थान, महत्वपूर्ण संपत्ति या सक्रिय व्यवसाय संचालन नहीं है।**

PatriotIAS

मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य चरण:

1. **प्लेसमेंट:** अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है (उदाहरण के लिए, बैंक खाते में जमा किया जाता है या संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है)।
2. **लेयरिंग:** धन को उनके अवैध मूल से दूर करने के लिए जटिल लेनदेन (अक्सर सीमाओं के पार) के माध्यम से ले जाया जाता है। इसमें कई खाते, शेल कंपनियां और वित्तीय उपकरण शामिल हो सकते हैं।
3. **एकीकरण:** लॉन्ड्र किए गए धन को वैध अर्थव्यवस्था में फिर से पेश किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे एक कानूनी स्रोत से आए हैं (उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट या व्यवसायों में निवेश किया गया)।

- **वे अक्सर ढीले नियमों और निरीक्षण के साथ गोपनीयता क्षेत्राधिकार में बनाए जाते हैं।**

कैसे शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती हैं?

- **स्वामित्व को अस्पष्ट करना: शेल कंपनियां अवैध धन के असली मालिकों (लाभकारी मालिकों) की पहचान छिपाती हैं।**
- **छिपाने वाले लेनदेन: इनका उपयोग लेनदेन का एक जटिल जाल बनाने के लिए किया जाता है जिससे धन की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण: विभिन्न देशों में शेल कंपनियाँ सीमाओं के पार धन ले जा सकती हैं, जिससे इसे ट्रैक करना और भी कठिन हो जाता है।**

- **भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बांड योजना के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके बावजूद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ाया।**
- साढ़े पांच वर्षों में, राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये नकद कमाए, जिसमें भाजपा को बहुमत मिला।
- जबकि अपारदर्शी योजना को समाप्त करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है, प्रत्येक चुनाव से पहले संदिग्ध स्रोतों से महत्वपूर्ण दान अभियान वित्तपोषण के मुद्दों को उजागर करते हैं।
- **चुनाव के बाद दाताओं और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान और संभावित कानून-तोड़ने की गहन जांच करना महत्वपूर्ण है।**
- न्यायपालिका को इन संस्थानों से कार्रवाई करने का आग्रह करना चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अभियान और चुनावी वित्तपोषण की सफाई आवश्यक है।

' के लिए समग्र दृष्टिकोण का आगमन (11 अप्रैल)

(GS PAPER II: स्वास्थ्य क्षेत्र)

'राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन' इस मान्यता का परिणाम है कि केवल एक समन्वित दृष्टिकोण ही बीमारी के प्रकोप पर बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा

- कोविड-19 जैसी महामारी के उद्भव ने **मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को उजागर किया है।**
- **गांठदार त्वचा रोग जैसे** प्रकोप के साथ देखा जाता है ।

गांठदार त्वचा रोग

Patriotic

- गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करती है।
- यह लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के कारण होता है, जो कैप्रीपॉक्सवायरस जीनस का एक पॉक्सवायरस है।
- इस रोग की विशेषता त्वचा और शरीर के अन्य भागों (त्वचा, आंतरिक अंग और श्लेष्म झिल्ली) पर कई गांठों का विकास है।

एलएसडी के लक्षण:

- तेज़ बुखार
- बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स
- त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर एकाधिक नोड्यूल (2-5 सेमी)।
- अंगों में सूजन के कारण लंगड़ापन
- दूध उत्पादन में कमी
- वजन घटना
- गंभीर मामलों में, मृत्यु (विशेषकर बिना टीकाकरण वाले या कम प्रतिरक्षा वाले जानवरों में)

एलएसडी का संचरण:

- गांठदार त्वचा रोग निम्नलिखित द्वारा प्रसारित हो सकता है:
  - खून चूसने वाले कीड़े जैसे मक्खियाँ, मच्छर और टिक
  - संक्रमित और स्वस्थ जानवरों के बीच सीधा संपर्क
  - दूषित फ़ोमाइट्स (वस्तुएँ या सामग्रियाँ जिनमें संक्रामक एजेंट हो सकते हैं)
  - संक्रमित एरोसोल का साँस लेना
  - माँ से संतान में अपरा संचरण

रोकथाम एवं नियंत्रण:

- एलएसडी को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है।
- प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए संगरोध उपाय और आवाजाही पर प्रतिबंध प्रसार को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
- वायरस फैलाने वाले कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है।

PatriotICIAS

- **'नेशनल वन हेल्थ मिशन'** पर कैबिनेट का फैसला इस अंतर्संबंध को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन

- **नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) द्वारा शुरू की गई** एक व्यापक पहल का उद्देश्य जूनोटिक बीमारियों (जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारियां) और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- यह अधिक समग्र रोग नियंत्रण और महामारी तैयारी रणनीति बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मौजूदा कार्यक्रमों का लाभ उठाता है।

मिशन के उद्देश्य:

- **अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना:** एकीकृत प्रतिक्रिया के लिए मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्रों को एक साथ लाना।

- **क्षमता निर्माण:** रोग निगरानी, निदान और रोकथाम के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- **एक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना:** जूनोटिक रोगों और एएमआर को समझने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- **महामारी संबंधी तैयारियों को बढ़ाना:** भविष्य की महामारियों की पहचान करने, रोकथाम करने और प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं में सुधार करना।

- जुलाई 2022 में, **प्रधान मंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) ने** मिशन की स्थापना का समर्थन किया।
- **विभाग , जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सहित विज्ञान वित्त पोषण एजेंसियों के साथ तेरह मंत्रालय और विभाग , मिशन को आकार देने के लिए एक साथ आए।**
- **इसमें शामिल मंत्रालयों में स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण, रक्षा और आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) शामिल हैं।**
- मिशन **वन हेल्थ और महामारी संबंधी तैयारियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है ।**
- **एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान** स्थापित करने पर सहमति बनी ।
- **नागपुर में स्थित,** संस्थान **राष्ट्रीय गतिविधियों के समन्वय के लिए एंकर और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।**
- संस्थान की आधारशिला 11 दिसंबर, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी।

और अधिक एक यात्रा

- **'राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन' का लक्ष्य है:**
  - एकीकृत रोग निगरानी और संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया के लिए रणनीतियाँ विकसित करें।
  - अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रयासों का समन्वय करें।
  - नियमित और महामारी दोनों बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निर्बाध जानकारी साझा करना सुनिश्चित करें।
  - जानवरों को प्रभावित करने वाली बीमारियाँ, जैसे पैर और मुँह की बीमारी या गांठदार त्वचा रोग, उत्पादकता और व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं।
  - कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारियाँ जंगली जानवरों और उनके संरक्षण को भी प्रभावित करती हैं।
- **एक समन्वित दृष्टिकोण** एवियन इन्फ्लूएंजा या निपाह जैसी बीमारियों के लिए तैयारी करना आवश्यक है **, जो अगली महामारी का कारण बन सकती हैं।**

निपाह वायरस (NiV)

- निपाह वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ इसका प्राकृतिक भंडार हैं।
- NiV जानवरों और मनुष्यों दोनों में गंभीर बीमारी का कारण बनता है, जिसकी मृत्यु दर उच्च है (मामले में मृत्यु दर 40-75% के बीच अनुमानित है)।
- लक्षण स्पर्शोन्मुख (कोई लक्षण नहीं) से लेकर तीव्र श्वसन बीमारी और घातक एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) तक होते हैं।

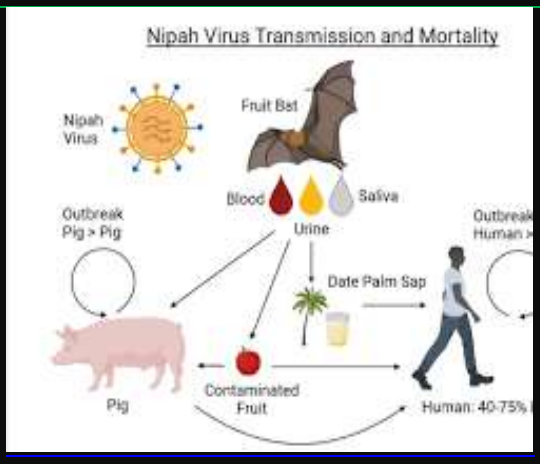

PatriotICIAS

प्रकोप का इतिहास

- **पहला प्रकोप:** इस बीमारी की पहचान सबसे पहले 1999 में मलेशिया और सिंगापुर के सुअर पालकों में हुई थी।
- **इसके बाद का प्रकोप:** तब से, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में इसका प्रकोप लगभग हर साल होता रहा है।

हालिया प्रकोप (भारत और बांग्लादेश)

- **केरल, भारत (2018, 2021, 2023):** इन वर्षों में केरल राज्य में कई मामले और मौतें दर्ज की गईं।
- **बांग्लादेश:** बांग्लादेश में लगभग वार्षिक प्रकोप का अनुभव होता है, जिसमें चिंताजनक आवृत्ति के साथ मामले सामने आते हैं।

हस्तांतरण

- **पशु से मनुष्य:** संक्रमित जानवरों (सूअर, चमगादड़) या उनके शारीरिक तरल पदार्थ के साथ संपर्क। चमगादड़ के उत्सर्जन से दूषित खजूर के रस का सेवन बांग्लादेश में एक प्रमुख मार्ग रहा है।
- **मानव-से-मानव:** संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के निकट संपर्क के माध्यम से संचरण हो सकता है।

रोकथाम

- **कोई विशिष्ट टीका नहीं: वर्तमान में,** मनुष्यों में NiV संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट टीका या उपचार मौजूद नहीं है । रोकथाम काफी हद तक इस पर निर्भर करती है:
  - स्थानिक क्षेत्रों में बीमार जानवरों के संपर्क से बचना।
  - अच्छी स्वच्छता अपनाएं और फलों को अच्छी तरह से धोएं, विशेषकर खजूर के रस को।
  - आगे के संचरण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाना और अलग करना।

खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी)?

- एफएमडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से मवेशी, सूअर, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं सहित दो खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है।
- यह तेजी से फैलता है और पशुधन उद्योग को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है।
- जबकि वयस्क जानवरों में यह शायद ही कभी घातक होता है, युवा जानवरों में यह गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है।

एफएमडी के नैदानिक लक्षण:

- तेज़ बुखार
- मुँह, जीभ, स्तनों और खुरों पर छाले जैसे घाव
- अत्यधिक लार निकलना और लार टपकना
- लंगड़ापन और हिलने-डुलने में अनिच्छा
- दूध उत्पादन में कमी
- वजन घटना

ट्रांसमिशन:

- शारीरिक तरल पदार्थ (लार, नाक से स्राव, दूध) के माध्यम से संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क।
- दूषित वस्तुओं और सतहों (कृषि उपकरण, वाहन, आदि) के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क।

PoliticIAS

- कम दूरी पर हवाई प्रसारण संभव है।

एफएमडी का प्रभाव:

- व्यापार प्रतिबंधों, उत्पादन में कमी और जानवरों की हत्या के कारण आर्थिक नुकसान।
- पशुधन उद्योग और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का विघटन।

रोकथाम एवं नियंत्रण:

- **टीकाकरण:** प्रभावी टीके उपलब्ध हैं और एफएमडी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जैव सुरक्षा उपाय:** सख्त संगरोध प्रक्रियाएं, आवाजाही प्रतिबंध और कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल।
- **मारना:** कुछ मामलों में, संक्रमित और उजागर जानवरों को मारने से प्रकोप को रोकने में मदद मिलती है

- **मजबूत अनुसंधान एवं विकास प्रयास** टीके, उपचार विज्ञान और निदान विकसित करने सहित महामारी संबंधी तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **शामिल विभागों में शामिल हैं** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), और फार्मास्यूटिकल्स विभाग।
- **शैक्षणिक केंद्र और निजी क्षेत्र भी इस प्रयास में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।**
- **केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय** प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है।
- राज्यों के साथ काम करने से जमीनी स्तर पर वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने और कार्यान्वयन पाठों के आधार पर रणनीति को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी।

प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क

- नेशनल **वन हेल्थ मिशन' ने उच्च जोखिम वाले रोगज़नक़ प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें जैव सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल 3) और जैव सुरक्षा स्तर 4 (बीएसएल 4) सुविधाएं शामिल हैं।**
- **विभिन्न विभागों द्वारा प्रबंधित इन प्रयोगशालाओं को एक साथ लाने से मानव, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों में रोग फैलने की प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है।**
- यह एकीकृत दृष्टिकोण **संसाधन उपयोग में सुधार करता है और निपाह वायरस के प्रकोप जैसी कई प्रजातियों से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।**
- मिशन के तहत भारत का लक्ष्य अपनी महामारी विज्ञान और डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत करना है।
- प्रयासों में **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और रोग मॉडलिंग को लागू करना शामिल है।**
- सभी क्षेत्रों में महामारी विज्ञान में क्षमता निर्माण का समन्वय किया जा रहा है।
- जैसी उभरती तकनीकों का विस्तार किया जाएगा **, जिसने COVID-19 महामारी के दौरान वादा दिखाया था ।**
- **यह विस्तार विभिन्न प्रहरी साइटों को कवर करेगा, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां जानवर (पशुधन या वन्यजीव) इकट्ठा होते हैं, ताकि मानव, पशुधन और पर्यावरणीय डोमेन में बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला की निगरानी की जा सके।**

एक वैश्विक विषय

- **भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान, 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया और सभी सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया।**

PatriotICIAS

- लक्ष्य बेहतर निगरानी क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता के निर्माण और 'वन हेल्थ' संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने पर सहयोग करना है।
- 'वन हेल्थ' बीमारियों से परे रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य सुरक्षा, पौधों की बीमारियों और इन पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे व्यापक मुद्दों को शामिल करता है।
- 'वन हेल्थ' चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और नागरिकों को शामिल करने वाला अंतरक्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है ।
- **'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' और 'सभी के लिए स्वास्थ्य'** पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक कार्रवाई योग्य रूपरेखा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर सकते हैं।

प्रबंधन अध्ययन के लिए आईआईएम-ए दुनिया के शीर्ष 25 में शामिल; जेएनयू को भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा (11 अप्रैल)

- विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा की गई, और भारतीय संस्थानों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद को व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 25 में स्थान दिया गया है।
- आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता को विश्व स्तर पर शीर्ष 50 में स्थान दिया गया है।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है, जो विकास अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल करता है।
- चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर है।
- भारत को बढ़ती मांग के कारण उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक शिक्षा प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- हालाँकि, विषय रैंकिंग में प्रदर्शित भारतीय कार्यक्रमों की संख्या 355 से 454 तक बढ़ने से आश्वासन मिला है।
- व्यापक एशियाई क्षेत्रीय संदर्भ में, भारत विश्वविद्यालयों की संख्या (69) के मामले में चीन (101) से पीछे दूसरे स्थान पर है।
- चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत कुल रैंक वाली प्रविष्टियों (454) में चौथे स्थान पर है।
- शीर्ष 200 प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत क्षेत्रीय स्तर पर पांचवें स्थान पर है।

भारतीय राज्यों में बेरोजगारी पर (11 अप्रैल)

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में दो-तिहाई बेरोजगार व्यक्ति युवा स्नातक हैं, जो नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है।
- रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी के कारणों के बारे में समझ की कमी को उजागर करती है, इस ज्ञान अंतर को संबोधित करने की तात्कालिकता पर जोर देती है।

PatriotICIAS

- विश्लेषण 2022-23 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के डेटा का उपयोग करते हुए, भारत के प्रमुख राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी पर केंद्रित है।
- मणिपुर में संघर्ष के कारण फील्डवर्क पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसे विश्लेषण से बाहर रखा गया है।
- नमूने में छोटे राज्यों का कवरेज बड़े राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इसलिए प्रदान किए गए अनुमानों को बेरोजगारी कारकों के निश्चित माप के बजाय संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिए।

बेरोजगारी का एक विश्लेषण

- चित्र 1 वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय राज्यों में बेरोजगारी दर को दर्शाता है, जो उच्चतम से निम्नतम तक व्यवस्थित है।
- गोवा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक लगभग 10% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.17% से तीन गुना अधिक है।
- दिलचस्प बात यह है कि उच्च बेरोजगारी दर वाले शीर्ष पांच राज्यों में से चार (गोवा, केरल, हरियाणा और पंजाब) तुलनात्मक रूप से समृद्ध राज्य हैं।
- महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पश्चिमी भारतीय राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।
- कर्नाटक को छोड़कर सभी उत्तरी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) और अधिकांश दक्षिणी राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- विचार किए गए 27 राज्यों में से 12 राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बेरोजगारी दर कम होने के बावजूद, एक पहेली है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर, राष्ट्रीय औसत से कम दर वाले कई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

बेरोजगारी के निर्धारक

- स्व-रोज़गार में शामिल श्रम बल की हिस्सेदारी के बीच संबंध को दर्शाता है ।
- चित्र 2 में प्रवृत्ति रेखा नीचे की ओर झुकती है, जो एक नकारात्मक संबंध का संकेत देती है: स्व-रोज़गार के उच्च अनुपात वाले राज्यों में बेरोजगारी दर कम होती है।
- चूँकि भारत में अधिकांश स्व-रोज़गार अनौपचारिक है, इसलिए महत्वपूर्ण अनौपचारिक कार्यबल वाले राज्य आसानी से नौकरी चाहने वालों को शामिल कर सकते हैं।
- हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह संबंध कारणात्मक है या नहीं। क्या स्व-रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण उच्च बेरोज़गारी होती है, या क्या उच्च बेरोज़गारी दर वाले राज्य व्यक्तियों को स्व-रोज़गार अपनाने से रोकते हैं?
- अनौपचारिक स्व-रोज़गार बड़े पैमाने पर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए, श्रम बल की शहरी हिस्सेदारी की जांच से अंतर्दृष्टि मिलती है।
- श्रम बल की शहरी हिस्सेदारी और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को दर्शाता है।
- एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध है, जो अत्यधिक शहरीकृत राज्यों में उच्च बेरोजगारी दर का संकेत देता है।
- यह बताता है कि क्यों गोवा और केरल जैसे राज्य, जो अत्यधिक शहरीकृत हैं, उच्च बेरोजगारी दर का अनुभव करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश (यूपी), झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कम दर है।
- शहरीकृत राज्यों में छोटे कृषि क्षेत्र हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अनौपचारिक रोजगार के कम अवसर मिलते हैं, जहां कृषि अनौपचारिक रोजगार के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है।

शिक्षा और रोजगार पर

PatriotIAS

- अत्यधिक शहरीकृत होने के बावजूद, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में बेरोजगारी दर कम है, जहां शहरी श्रम शक्ति हिस्सेदारी कम है।
- ILO-IHD रिपोर्ट की चर्चा शिक्षा और बेरोजगारी के बीच संबंध पर केंद्रित है।
- चित्र 4 भारतीय राज्यों में इस सहसंबंध को दर्शाता है, जो एक स्पष्ट सकारात्मक संबंध दर्शाता है।
- श्रम शक्ति (30% स्नातक हैं) वाला केरल उच्च बेरोजगारी का अनुभव करता है।
- श्रम शक्ति में स्नातकों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है (क्रमशः 14% और 20%) और परिणामस्वरूप अमीर और शहरीकृत होने के बावजूद बेरोजगारी दर कम है।
- कई कारण इस परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि स्नातकों के पास आधुनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल की कमी है, जो बेहतर शिक्षण बुनियादी ढांचे और मानकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- एक और स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि स्नातक अपने कौशल के अनुरूप उच्च वेतन वाली नौकरियों की आकांक्षा रखते हैं, और यदि आधुनिक क्षेत्र उन्हें अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तार नहीं करता है, तो बेरोजगारी का परिणाम होता है।
- राज्य की नीतियां भी बेरोजगारी दर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- चूँकि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रही हैं, कृषि की भूमिका में कमी और शहरीकरण और शैक्षिक प्राप्ति में वृद्धि के साथ, बेरोजगारी दर पर दबाव बढ़ रहा है।
- इन प्रवृत्तियों का प्रतिकार करने और बेरोजगारी को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नीति का ध्यान रोजगार सृजन पर होना चाहिए।

ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने पर प्रमुख धर्म अलग-अलग रुख अपनाते हैं (11 अप्रैल)

- वेटिकन **ने एक नया दस्तावेज़ जारी किया जिसमें किसी के जैविक लिंग को बदलने की अवधारणा को खारिज कर दिया गया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निराशा हुई, जिन्होंने पोप फ्रांसिस के तहत कैथोलिक चर्च से अधिक स्वागत योग्य दृष्टिकोण की उम्मीद की थी** ।
- लिंग परिवर्तन के प्रति यह निराशाजनक रुख केवल कैथोलिक चर्च के लिए ही नहीं है; अन्य संप्रदाय, जैसे कि दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन, यह भी दावा करते हैं कि भगवान के डिजाइन में दो अलग और पूरक लिंग शामिल हैं - पुरुष और महिला - जो जैविक लिंग द्वारा निर्धारित होते हैं, आत्म-धारणा से नहीं।
- हालाँकि, कुछ मुख्य प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जैसे **इवेंजेलिकल लूथरन चर्च** अमेरिका में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सदस्यों और पादरी के रूप में स्वागत है। वास्तव में, उन्होंने 2021 में एक खुले तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिशप के रूप में चुना।
- इस्लाम में, एक भी केंद्रीय धार्मिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए ट्रांसजेंडर मुद्दों पर नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं। काहिरा में अल-अजहर की वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के महासचिव अब्बास शौमन ने कहा कि **उनके विचार में लिंग परिवर्तन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि यह भगवान की रचना के खिलाफ है।**
- ईरान में, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने दशकों पहले एक फतवा जारी किया था, जिसमें शिया धर्मतंत्र के ढांचे के भीतर लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए आधिकारिक समर्थन की अनुमति दी गई थी।

सहस्राब्दियों से मान्यता प्राप्त है

PatrioticIAS

- दक्षिण एशिया में हिंदू समाज में, पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाएँ निर्धारित हैं, लेकिन गैर-द्विआधारी लिंग अभिव्यक्ति के लोगों को सहस्राब्दियों से मान्यता दी गई है और उन्होंने पवित्र ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं।
- पूरे दक्षिण एशियाई इतिहास में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सम्मान किया गया है, जिनमें से कई ने हिंदू और मुस्लिम शासकों के अधीन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं। 2014 में एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि **अकेले भारत में लगभग 30 लाख ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं।**
- हिंदू धर्मग्रंथों की प्राचीन भाषा संस्कृत में तीन लिंगों का वर्णन करने की शब्दावली है - पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लिंग-तटस्थ।
- कुछ हिंदुओं का मानना है कि ट्रांसजेंडर **लोगों के पास विशेष शक्तियां और आशीर्वाद देने या श्राप देने की क्षमता होती है, जिससे समुदाय में रूढ़िवादिता पैदा होती है और भय और हाशिये पर डाल दिया जाता है।** कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल, आवास और रोजगार तक उचित पहुंच के बिना गरीबी में रहते हैं।
- **2014 में, भारत, नेपाल और बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर लोगों को समान अधिकारों के योग्य नागरिक के रूप में मान्यता दी।**
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अपना लिंग चुनना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, इस बात पर जोर देते हुए कि समूह की मान्यता एक मानवाधिकार मुद्दा है, न कि केवल एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा।
- **सुधार यहूदी धर्म ट्रांसजेंडर लोगों को स्वीकार कर रहा है और ट्रांसजेंडर रब्बियों के समन्वय की अनुमति देता है।**
- यहूदी पारंपरिक ज्ञान आम तौर पर जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग से जुड़े लोगों से परे लिंग पहचान और अभिव्यक्ति की खोज की अनुमति देता है, जैसा कि कबला जैसे रहस्यमय ग्रंथों में परिलक्षित होता है।

रूढ़िवादी विचार

- **द्विआधारी लिंग और पुरुषों और महिलाओं के बीच सख्त अलगाव पर जोर देने के कारण रूढ़िवादी यहूदी धर्म अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है।**
- ट्रांसजेंडर लोगों को रूढ़िवादी समुदायों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यह **निर्धारित करना कि पूजा के दौरान कहाँ बैठना है यदि उनमें चिकित्सकीय रूप से संक्रमण नहीं हुआ है।**
- अमेरिका के अगुडथ इज़राइल के रब्बी एवी शफ़रान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहूदी धार्मिक कानून जन्म के समय निर्धारित लिंग के अनुसार रहने का निर्देश देता है।
- बौद्ध धर्म में, द्विआधारी लिंग भूमिकाओं का पारंपरिक पालन प्रचलित है, विशेष रूप से मठवासी परंपराओं में जहां पुरुषों और महिलाओं को अलग किया जाता है और विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जाती हैं।
- थाई **संघ परिषद ने थेरवाद बौद्ध धर्म** में मजबूत द्विआधारी लिंग मान्यताओं को दर्शाते हुए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अभिषेक पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया ।
- हालाँकि, कुछ थेरवाद परंपराओं ने जन्म के समय दर्ज किए गए लिंग के आधार पर गैर-अनुरूप लिंग वाले व्यक्तियों को नियुक्त करके प्रतिबंधों को कम कर दिया है।
- **बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदाय अधिक लचीले हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपवाद की अनुमति देते हैं, जबकि जोडो शिंशु संप्रदाय** ट्रांसजेंडर भिक्षुओं को नियुक्त करने में विशेष रूप से शामिल है।

PatriotiCAS

- तिब्बती बौद्ध धर्म में, ताशी चोएदुप , एक खुले तौर पर विचित्र भिक्षु, को उनकी लिंग पहचान के बारे में पूछे बिना नियुक्त किया गया था, जो बौद्ध सिद्धांत के अनुरूप था जो लिंग पर आध्यात्मिक गुणों को प्राथमिकता देता है।
- कई बौद्ध संप्रदाय, विशेष रूप से पश्चिम में, जानबूझकर ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी सभाओं या संघों में शामिल करते हैं ।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सी निचली ट्रॉलिंग से जुड़ी प्रत्यक्ष पर्यावरणीय चिंता है?
(ए) मूंगा चट्टान की वृद्धि में वृद्धि
(बी) लक्षित मछली स्टॉक का ह्रास
(सी) समुद्री जल की लवणता में कमी
(डी) फाइटोप्लांकटन आबादी में गिरावट

प्रश्न 2: बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इससे समुद्री आवासों का विनाश हो सकता है।
2. मछली की गैर-लक्षित प्रजातियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी शेल कंपनियों की एक सामान्य विशेषता है, जो अक्सर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आकर्षक उपकरण बनाती है?
(ए) कई देशों में व्यापक व्यापार संचालन
(बी) पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं
(सी) भौतिक उपस्थिति का अभाव और न्यूनतम आर्थिक गतिविधि
(डी) वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन

प्रश्न 4: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मुख्य रूप से काम करता है:
(ए) अंतरराष्ट्रीय प्रेषण भुगतान की सुविधा प्रदान करना।
(बी) मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करें।
(सी) क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को विनियमित करें।
(डी) कर चोरी के मामलों की जांच करना।

प्रश्न 5: गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है?
(ए) मुर्गीपालन
(बी) मवेशी
(सी) बकरी और भेड़
(डी) सूअर

प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग का एक सामान्य लक्षण है?
(ए) अत्यधिक पसीना आना
(बी) लगातार छींक आना
(सी) त्वचा पर गांठों का बनना
(डी) पूंछ काटना और बेचैनी

प्रश्न 7: लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) किस वायरस परिवार से संबंधित है?
(ए) पॉक्सविरिडे
(बी) रेट्रोविरिडे
(सी) एडेनोविरिडे

PerioticIAS

(डी) हर्पीसविरिडे

प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ (एनआईओएच) के फोकस का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(ए) उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए टीकों का अनुसंधान और विकास।
(बी) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
(सी) ज़ूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर समन्वय और अनुसंधान।
(डी) नई फार्मास्युटिकल दवाओं की नियामक निगरानी और अनुमोदन।

प्रश्न 9: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की स्थापना किस व्यापक पहल के उद्देश्यों से मेल खाती है?
(ए) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
(बी) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
(सी) राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन
(डी) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

प्रश्न 10: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।
2. यह अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ सहयोग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 11: खुरपका-मुँहपका रोग किसके कारण होता है?
(ए) बैक्टीरिया
(बी) कवक
(सी) प्रोटोजोआ परजीवी
(डी) वायरस

प्रश्न 12: खुरपका-मुंहपका रोग का संचरण किसके माध्यम से नहीं हो सकता:
(ए) संक्रमित जानवरों से सीधा संपर्क
(बी) दूषित फ़ीड
(सी) मच्छर का काटना
(डी) कम दूरी पर हवा में उड़ने वाले कण

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सी निचली ट्रॉलिंग से जुड़ी प्रत्यक्ष पर्यावरणीय चिंता है? (ए) मूंगा चट्टान की वृद्धि में वृद्धि (बी) लक्षित मछली स्टॉक का ह्रास (सी) समुद्री जल की लवणता में कमी (डी) फाइटोप्लांकटन आबादी में गिरावट	उत्तर: (बी) लक्षित मछली भंडार का ह्रास स्पष्टीकरण: विकल्प (ए) गलत है: निचली ट्रॉलिंग मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचा सकती है, न कि उनकी वृद्धि को बढ़ा सकती है। विकल्प (बी) सही है: अस्थिर निचली ट्रॉलिंग के कारण अत्यधिक मछली पकड़ने से इच्छित पकड़ की आबादी कम हो सकती है। विकल्प (सी) गलत है: निचली ट्रॉलिंग का समग्र समुद्री जल की लवणता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। विकल्प (डी) गलत है: जबकि निचली ट्रॉलिंग समुद्र तल को बाधित कर सकती है, फाइटोप्लांकटन पर इसका प्रभाव मछली स्टॉक की तरह सीधा नहीं है।
प्रश्न 2: बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इससे समुद्री आवासों का विनाश हो सकता है।	उत्तर (ए): केवल 1 स्पष्टीकरण:

PatrioticIAS

2. मछली की गैर-लक्षित प्रजातियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	**कथन 1** सही है. निचली ट्रॉलिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला भारी गियर समुद्र तल पर नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। **कथन 2** गलत है. निचली ट्रॉलिंग के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बायकैच (गैर-लक्ष्य प्रजातियाँ) पकड़ी जाती हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता को नुकसान होता है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी शेल कंपनियों की एक सामान्य विशेषता है, जो अक्सर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आकर्षक उपकरण बनाती है? (ए) कई देशों में व्यापक व्यापार संचालन (बी) पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं (सी) भौतिक उपस्थिति का अभाव और न्यूनतम आर्थिक गतिविधि (डी) वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन	उत्तर: (सी) भौतिक उपस्थिति का अभाव और न्यूनतम आर्थिक गतिविधि स्पष्टीकरण: शेल कंपनियां अक्सर बहुत कम या कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के साथ स्थापित की जाती हैं, जिससे अवैध लेनदेन को छिपाना आसान हो जाता है। विकल्प (ए), (बी), और (डी) मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग की जाने वाली शेल कंपनियों की विशिष्ट विशेषताएं नहीं हैं।
प्रश्न 4: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मुख्य रूप से काम करता है: (ए) अंतरराष्ट्रीय प्रेषण भुगतान की सुविधा प्रदान करना। (बी) मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करें। (सी) क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को विनियमित करें। (डी) कर चोरी के मामलों की जांच करना।	उत्तर: (बी) मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करें। **स्पष्टीकरण:** एफएटीएफ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए नीतियों को विकसित और बढ़ावा देता है।
प्रश्न 5: गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) मुख्य रूप से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? (ए) मुर्गीपालन (बी) मवेशी (सी) बकरी और भेड़ (डी) सूअर	उत्तर: (बी) मवेशी स्पष्टीकरण: जबकि एलएसडी कभी-कभी एशियाई जल भैंस जैसी अन्य प्रजातियों में भी हो सकता है, इसका प्राथमिक लक्ष्य मवेशी हैं।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग का एक सामान्य लक्षण है? (ए) अत्यधिक पसीना आना (बी) लगातार छींक आना (सी) त्वचा पर गांठों का बनना (डी) पूंछ काटना और बेचैनी	उत्तर: (सी) त्वचा पर गांठों का बनना स्पष्टीकरण: त्वचा पर विशिष्ट गांठें या गांठें एलएसडी का एक प्रमुख लक्षण हैं, जो इस बीमारी को इसका नाम देता है।
प्रश्न 7: लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) किस वायरस परिवार से संबंधित है? (ए) पॉक्सविरिडे (बी) रेट्रोविरिडे (सी) एडेनोविरिडे (डी) हर्पीसविरिडे	उत्तर: (ए) पॉक्सविरिडे स्पष्टीकरण: एलएसडीवी पॉक्सविरिडे परिवार का एक सदस्य है, जिसमें चेचक और मंकीपॉक्स जैसे वायरस भी शामिल हैं।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ (एनआईओएच) के फोकस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? (ए) उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए टीकों का अनुसंधान और विकास।	उत्तर: (सी) जूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर समन्वय और अनुसंधान। स्पष्टीकरण: एनआईओएच एक केंद्रीय संस्थान है जिसे मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

PatriotIAS

(बी) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। (सी) ज़ूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर समन्वय और अनुसंधान। (डी) नई फार्मास्युटिकल दवाओं की नियामक निगरानी और अनुमोदन।	
प्रश्न 9: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की स्थापना किस व्यापक पहल के उद्देश्यों से मेल खाती है? (ए) राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (बी) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) (सी) राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन (डी) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	उत्तर: (सी) राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन स्पष्टीकरण: एनआईओएच मिशन के तहत अनुसंधान, क्षमता निर्माण और समन्वय के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करना है।
प्रश्न 10: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 3. यह नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। 4. यह अंतर्राष्ट्रीय वन हेल्थ सहयोग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (ए) केवल 1 (बी) केवल 2 (सी) 1 और 2 दोनों (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर : (सी) 1 और 2 दोनों स्पष्टीकरण: आपके द्वारा दिए गए इनपुट में एनआईओएच का स्थान और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय में भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।
प्रश्न 11: खुरपका-मुँहपका रोग किसके कारण होता है? (ए) बैक्टीरिया (बी) कवक (सी) प्रोटोजोआ परजीवी (डी) वायरस	उत्तर: (डी) वायरस स्पष्टीकरण: खुरपका-मुंहपका रोग वायरस (एफएमडीवी) पिकोर्नविरिडे परिवार से संबंधित है।
प्रश्न 12: खुरपका-मुंहपका रोग का संचरण किसके माध्यम से नहीं हो सकता: (ए) संक्रमित जानवरों से सीधा संपर्क (बी) दूषित फ़ीड (सी) मच्छर का काटना (डी) कम दूरी पर हवा में उड़ने वाले कण	उत्तर: (सी) मच्छर के काटने से स्पष्टीकरण: एफएमडीवी मच्छरों द्वारा प्रसारित नहीं होता है। मुख्य मार्गों में सीधा संपर्क, दूषित वस्तुओं से संपर्क और कभी-कभी कम दूरी का हवाई संचरण शामिल है।

PatrioticIAS